

मुकदमों का विवरण

मेसर्स यूनिब्रोस बनाम.

ऑल इंडिया रेडियो

(सिविल अपील सं. 6895/2023) अक्टूबर 19, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: यदि मध्यस्थता का निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के साथ मेल खाता है और क्या लाभ के नुकसान के कारण कोई प्रश्न केवल इस आधार पर सफल होने के लिए उत्तरदायी है कि निर्माण अनुबंध के निष्पादन में देरी हुई है, जो नियोक्ता के कारण है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34 (2) (बी)-"भारत की सार्वजनिक नीति"-अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा कार्य अनुबंध प्रदान किया गया-कार्य में देरी के कारण पक्षों के बीच विवाद, जिसे मध्यस्थ को संदर्भित किया गया-प्रथम पुरस्कार के माध्यम से, अपीलार्थी को लाभ के नुकसान के लिए राशि प्रदान की गई (दावा No.12)-उच्च न्यायालय द्वारा अलग रखा गया पुरस्कार, मध्यस्थ को भेजे गए दावे-दूसरा पुरस्कार अपीलार्थी को लाभ और ब्याज के नुकसान के लिए पुरस्कार को बनाए रखते हुए पारित किया गया था। 34 दूसरे अधिनिर्णय अपास्त करते हुए के लिए-एकल न्यायाधीश ने आपत्ति को अनुज्ञात कर लिया, अपीलार्थी के दावे को अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया कोई पर्याप्त सबूत नहीं था जो डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आदेश के लाभ के नुकसान के दावे को स्थापित कर सके:

आयोजित किया गया: दूसरा पुरस्कार प्रथम पुरस्कार के रूप में भारत की सार्वजनिक नीति के साथ समान रूप से जुड़ा हुआ है-पुनर्विचार के लिए दावा No.12 को प्रेषित करते समय, मध्यस्थ को चेतावनी दी गई थी कि वह उन कारकों से प्रभावित न हो जो पहला पुरस्कार देते समय उनके दिमाग में थे-मध्यस्थ को भी केवल साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी-हालाँकि, मध्यस्थ ने उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय को दंड से मुक्ति के साथ नजरअंदाज कर दिया-पहले दौर और दूसरे दौर में मध्यस्थ के दिमाग में जिन कारकों का भार था, वे एक ही हैं-684 के ब्रांड होने के किसी भी आरोप से बचने के लिए।

जहां तक दावे का संबंध है, प्रथम पुरस्कार की दर्पण छवि के रूप में, दूसरा पुरस्कार भाषा में व्यक्त किया गया प्रतीत होता है और पहले वाले से अलग रूप में व्यक्त किया गया है, हालांकि, सार में कोई बदलाव नहीं है-एक उच्च विधि के न्यायिक निर्णय, जो एक निम्न अदालत पर बाध्यकारी है, को निम्न अदालत द्वारा अनुग्रह के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, इसके बावजूद कि उच्च विधि का निर्णय निम्न अदालत के लिए रुचिप्रश्न नहीं हो सकता है-यह सिद्धांत, विशेष रूप से एक मध्यस्थ और एक बहु-सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिप्रश्न पर भी लागू होगा, विशेष रूप से जब यह एक सीमित रिमांड का आदेश देने वाले न्यायिक निर्णय (अधिनियम की धारा 34 या धारा 37 के तहत) का सामना प्रश्नता है। 34(2)(ख) अपील में कोई योग्यता नहीं है।[पैरा 13,14 और 20]

मध्यस्थता-विलंबित अनुबंध या अन्य उपलब्ध अनुबंधों से चूक गए अवसरों से उत्पन्न होने वाले लाभ के नुकसान के लिए दावा-दावेदार को यह प्रदर्शित करने वाले सम्मोहक साक्ष्य के माध्यम से एक व्यवहार्य अवसर की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कि यदि अनुबंध को तुरंत निष्पादित किया गया होता, तो ठेकेदार अपने मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके पूरक लाभ प्राप्त कर सकता था-ऐसे साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता:

आयोजित किया गया:यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा- हालांकि, इसमें आम तौर पर स्वतंत्र समकालीन साक्ष्य शामिल हो सकते हैं जैसे कि ठेकेदार के पास पाइपलाइन में अन्य संभावित परियोजनाएं जो देरी के बिना शुरू की जा सकती थीं, अनुबंध के लंबे समय तक चलने के कारण ठेकेदार को प्राप्त और अस्वीकार किए गए निविदा अवसरों की कुल संख्या, वित्तीय विवरण, या देरी, समय बढ़ाने और लाभ के नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित अनुबंध में कोई भी खंड-यह सूची संपूर्ण नहीं है और इसमें कोई अन्य सबूत शामिल हो सकता है कि न्यायालय अंतिम रूप से प्रासंगिक हो सकती है-लाभ के नुकसान के दावे पर निर्णय लेने में, न्यायालय अंधेरे में अनुमान नहीं लगा सकती है; 685 की विश्वसनीयता।

साक्ष्य, इसलिए, ऐसे दावे की विश्वसनीयता का प्रमाण है-इस प्रकार, लाभ की हानि, लाभप्रदता या सफल होने के अवसरों से संबंधित दावों के लिए, किसी को यह स्थापित करने की आवश्यकता होगी कि अनुबंध के पूरा होने में देरी हुई थी; कि ऐसी देरी दावेदार के लिए जिम्मेदार नहीं है; कि दावेदार की स्थिति एक स्थापित ठेकेदार के रूप में है, जो पर्याप्त परियोजनाओं को संभाल रहा है; और लाभप्रदता के नुकसान के दावे को साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत-वर्तमान मामले में, चौथी शर्त, अर्थात्, लाभप्रदता के नुकसान के दावे को साबित करने के लिए सबूत अधूरे हैं।[पैरा 17,19]

मध्यस्थता-लाभ के नुकसान के लिए ठेकेदार के दावे-हडसन का सूत्र:

आयोजित किया गया:हडसन का सूत्र हालांकि स्वीकार्यता प्राप्त कर चुका है और व्यापार में अच्छी तरह से समझा जाता है, हालांकि, यह एक निर्वात में लागू नहीं होता है-हडसन का सूत्र, साथ ही साथ ऑफ-साइट ओवरहेड्स और लाभ के नुकसान के दावों की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य तरीके, सीधे ठेकेदार की सटीक लागत को नहीं मापते हैं-इसके बजाय, वे ठेकेदार के नुकसान का अनुमान प्रदान करते हैं जो पर्याप्त हो सकता है-हालांकि ये सूत्र आवश्यकता पड़ने पर सहायक होते हैं, वे अकेले ठेकेदार के लाभ के नुकसान को साबित नहीं कर सकते हैं-वे नुकसान का आकलन करने में उपयोगी होते हैं, लेकिन केवल तभी जब ठेकेदार ने सबूत के साथ लाभ के नुकसान और लंबे समय तक चलने के कारण पर्याप्त अवसरों को दिखाया हो।[पैरा 18]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

एसोसिएटेड बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एससीसी 49:2014 [13] एससीआर 895; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बनाम एल. के. आहूजा (2004) 5 एससीसी 109:2004 [3] एस. सी. आर. 1105; परियोजना निदेशक, एन. एच. ए. आई. बनाम एम. हकीम और एक अन्य (2021) 9 एस. सी. सी. 1:मेसर्स ए. टी. बृज पॉल सिंह और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1984) 4 एससीसी 59:मैकडर्मोट इंटरनेशनल इंक बनाममानक जलाएँ

कं. लिमिटेड और ओआरएस (2006) 11 एससीसी 181:2006 [2] पूरक।एससीआर 409; ओएनजीसी लिमिटेड बनाम.सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705:2003 [3] एस. सी. आर. 69-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील No.6895।2010 के एफ. ए. ओ. ओ. एस. No.229 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.12.2019 के निर्णय और आदेश से।

मेसर्स यूनिब्रॉस बनाम ऑल इंडिया रेडियो 686 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

रूप:

समीर रोहतगी, जगदीश वत्स, टी. एस. चौधरी, कार्तिकेय सिंह, सचिन गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

संजय जैन, ए. एस. जी., पीयूष बेरीवाल, सबरीश सुब्रमण्यन, श्रीमती बानी दीक्षित, राघव शर्मा, पद्मेश मिश्रा, टी. एस. सबरीश, सुश्री हर्षिता सुखीजा, अमरीश कुमार, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

दीपांकर दत्ता, जे।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील, मेसर्स यूनिब्रोस ("अपीलार्थी", इसके बाद) के कहने पर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम", इसके बाद) की धारा 37 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ("उच्च न्यायालय", इसके बाद) द्वारा पारित एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) 229/2010 में 9 दिसंबर, 2019 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, एक खंड पीठ ने 25 फरवरी, 2010 के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आकाशवाणी ("प्रतिवादी", इसके बाद) की आपत्ति को अनुज्ञात गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 15 जुलाई, 2002 के एक मध्यस्थ पुरस्कार अपास्त करते हुए कर दिया गया था, जिस हद तक कि उसने अपीलार्थी को लाभ का नुकसान घोषित किया था।

3. अभिलेख से ज्ञात प्रासंगिक तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा दिल्ली दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, चरण-2, नई दिल्ली के निर्माण के लिए एक कार्य अनुबंध दिया गया था। यह काम 12 अप्रैल, 1990 को शुरू होना था और 11 अप्रैल, 1991 को पूरा होना था; हालाँकि, इसमें लगभग साढ़े 42 महीने की देरी हुई और इसे 30 अक्टूबर, 1994 को पूरा किया गया। इस तरह की देरी के कारण पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिन्हें बाद में समाधान के लिए एक मध्यस्थ ("मध्यस्थ", इसके बाद) को भेजा गया। 4. वर्तमान चरण की ओर ले जाने वाले मामले का प्रक्षेपवक्र नीचे दिया गया है:

क) मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होने के बाद, मध्यस्थ ने 11 फरवरी, 1999 के निर्णय के माध्यम से (इसके बाद पहला पुरस्कार)

687

मेसर्स यूनिब्रोस बनाम ऑल इंडिया रेडियो दीपांकर दत्ता, जे.

पक्षों के नेतृत्व में विभिन्न दावों और प्रति-दावों का निर्णय लिया गया। दावा संख्या 10, 11 और 12 को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ("अनुबंध अधिनियम") की धारा 73 के अंतर्गत सामूहिक रूप से संबोधित किया गया था, क्योंकि वे सभी देरी और परिणामी नुकसान के मुद्दे पर केंद्रित थे। दावा संख्या 10 के माध्यम से, अपीलार्थी ने रुपये की राशि का दावा किया। निर्धारित अनुबंध अवधि के बाद निष्पादित कार्य के लिए कीमतों/दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण 50,00, (पचास लाख रुपये)। दावा संख्या 11 के माध्यम से, अपीलार्थी ने मध्यस्थ से रुपये देने का अनुरोध किया। 41, 00, (41 लाख रुपये) स्थापना, मशीनरी, सेंट्रिंग/शटरिंग और परियोजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े पर्याप्त खर्चों को कवर करने के लिए। इसके अतिरिक्त, दावा सं. 12 के माध्यम से, अपीलार्थी ने आग्रह किया कि मुआवजे के रूप में रु. 2,00,00,000.00 (दो करोड़ रुपये) अर्जित मौद्रिक लाभों में किसी भी अनुरूप वृद्धि के बिना अनुबंध पर अपीलार्थी के लंबे समय तक प्रतिधारण के कारण हुए

लाभ के नुकसान के निवारण के रूप में प्रदान किया जाए। मध्यस्थ द्वारा दावा संख्या 10 और 11 की अस्वीकृति के बावजूद, अपीलार्थी को रु। 12 मई, 1997 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक दावा संख्या 13 के अंतर्गत 18 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ दावा संख्या 12 के लिए 830 रुपये (एक करोड़, 44 लाख, 83 हजार, आठ सौ तीस रुपये)। मध्यस्थ ने इस निर्विवाद तथ्य के आधार पर इस पुरस्कार का समर्थन किया कि निर्धारित अनुबंध अवधि से परे काम को पूरा करने में देरी प्रतिवादी के कारण हुई थी और 12 महीने की निर्धारित अनुबंध अवधि के खिलाफ, अपीलार्थी को प्रतिवादी द्वारा साढ़े तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए काम के निष्पादन के लिए रखा गया था, जिससे उक्त विस्तारित अवधि के दौरान अपीलार्थी की लाभ कमाने की क्षमता का नुकसान हुआ। लाभ के नुकसान का अनुमान साढ़े सात प्रतिशत प्रति वर्ष के लाभ भत्ते के आधार पर लगाया गया था, जिसे मध्यस्थ ने सिविल कार्य अनुबंध में उचित माना था। हडसन के सूत्र को लागू करते हुए, मध्यस्थ लाभ के नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे पर पहुंचे, जिसकी गणना नीचे दी गई है:

देरी की अवधि	42.5 महीनों
अनुबंध मूल्य	रु. 5,45,27,386. 00
अनुबंध की अवधि	12 महीनों

688 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

ठेकेदार का लाभ (साढ़े सात प्रतिशत प्रति वर्ष) रु।	
40, 89, 554.00	
ठेकेदार का प्रति माह अपेक्षित लाभ	रु. 3, 40, 796.00
लाभ की कुल हानि	विलंब की कुल अवधि x ठेकेदार का अपेक्षित लाभ प्रति माह रु। 1,44,83,830. 00

ख) उअंतर्गत ोक्त प्रथम अधिनिर्णय से आहत होन्यायालय , मुख्य रूप से अपीलार्थी को लाभ की हानि के लिए रुपये, रुपये, रुपये, रुपये, रुपये, रुपये, रुपये, रुपये, रुपये, रुपये,

[illegible]

“24. *** हडसन के सूत्र और भवन और इंजीनियरिंग अनुबंधों पर पुस्तक विधि (एस. आई. सी., लॉ) के एक अंश को रिकॉर्ड पर रखने के अलावा, प्रतिवादी द्वारा यह दिखाने के लिए कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि लाभ के नुकसान के लिए दावा किया गया लाभ प्रतिशत उस समय यथार्थवादी था और इसके परिणामस्वरूप बाजार में कोई बदलाव नहीं हुआ था और यह भी कि कम से कम उसी सामान्य स्तर की लाभप्रदता का काम निर्धारित अनुबंध अवधि के अंत में प्रतिवादी को उपलब्ध होता। अतः उक्त दावे के संबंध में साक्ष्य निश्चित रूप से अभिलेख पर उपलब्ध नहीं प्रतीत होता है। किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में और जब दावा संख्या 10 और 11 के अंतर्गत दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि के बाद निष्पादित कार्य के लिए कीमतों/दरों में वृद्धि का संकेत देने वाला कोई पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था और साथ ही स्थापना, मशीनरी, केंद्रीकरण/शटर आदि के कारण भी, दावा No.12 को मध्यस्थता (sic, मध्यस्थ) द्वारा 689 पर विचार किए बिना अनुज्ञात गई थी।

मेसर्स यूनिब्रॉस बनाम ऑल इंडिया रेडियो दीपांकर दत्ता, जे.

क्या प्रत्यर्थी ने विश्वसनीय और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो साबित करने के लिए आवश्यक हैं।***

25. *** न केवल दावा No.12 के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए विश्वसनीय और आवश्यक साक्ष्य की कमी थी, जैसा कि विधि ऑफ बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के उद्धरणों में दिया गया है, और (एस. आई. सी.) मध्यस्थ ने ऐसे कारकों को भी ध्यान में रखा जो (एस. आई. सी.) उसके दिमाग को उत्तेजित कर सकते थे। इसलिए, अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (ii) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाली भारतीय विधि की मौलिक नीति के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार पारित किया गया था। मैं दावे के खिलाफ मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को अलग करता हूं और मध्यस्थ द्वारा पुनः विचार करने और उक्त दावे के संबंध में ऐसे कारकों द्वारा किसी भी तरह से प्रेरित किए बिना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक नया निर्णय पारित करने के लिए इसे प्रेषित

करता हूं। चूंकि मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक अलग रखा जाता है, इसलिए दावा संख्या 12 की राशि के संबंध में दावा संख्या 13 में ब्याज का अधिनिर्णय भी अलग रखा जाता है और रद्द कर दिया जाता है और उन्हें पुनर्विचार और निर्णय के लिए प्रेषित किया जाता है। पुरस्कार में उपरोक्त संशोधनों के अधीन, पुरस्कार के शेष भाग को बरकरार रखा जाता है। "

(ग) मध्यस्थ ने प्रथम पुरस्कार के माध्यम से अपीलार्थी को लाभ और ब्याज के नुकसान के लिए पुरस्कार बनाए रखते हुए 15 जुलाई, 2002 ("दूसरा पुरस्कार", इसके बाद) का एक नया पुरस्कार पारित किया। पक्षों के बीच संचार का उल्लेख करते हुए, मध्यस्थ ने दोहराया कि प्रतिवादी निर्धारित अनुबंध अवधि के भीतर पूरी साइट और चित्र प्रदान करने में विफल रहा, जिससे देरी हुई। स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, अनुबंध के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पक्ष उचित रूप से अनुमानित नुकसान के लिए उत्तरदायी है। पर्याप्त परियोजनाओं को संभालने वाले एक स्थापित ठेकेदार के रूप में अपीलार्थी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ ने अनुमान लगाया कि अपीलार्थी द्वारा कहीं और अपेक्षित लाभ की कमाई का अनुमान लगाना उचित था। इस सिद्धांत का उपयोग करना कि एक अनुबंध के भीतर, लाभ

690

/

[2023] 14 एस सी आर।

मध्यस्थ ने कहा कि अपीलार्थी को पूर्ण निश्चितता के साथ लाभ या हानि की सटीक राशि स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी; इसके बजाय, मामले की विशेष परिस्थितियों अंतर्गत काफी प्रेरक और सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

घ) प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत एक याचिका का नेतृत्व किया, जिसमें दूसरे पुरस्कार को रद्द करने की मांग की गई। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 25 फरवरी 2010 के निर्णय और अंतिम आदेश के माध्यम से धारा 34 के अंतर्गत आपत्ति को अनुज्ञात कर लिया और दावा संख्या 12 के अंतर्गत अपीलार्थी के दावे को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए लाभ के नुकसान को स्थापित करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। अनुबंध प्रदर्शन में पुरुषों, सामग्री, मशीनरी, ओवरहेड और अन्य संसाधनों के कथित उपयोग के बारे में अभिलेख की कमी, जिसका उपयोग अन्यथा अन्य प्रो टेबल अनुबंधों के लिए किया जा सकता था, ने दावा संख्या 12 के अंतर्गत दावा किए गए नुकसान की वैधता के बारे में संदेह पैदा किया। इस अवलोकन के साथ कि अपीलार्थी के गलत दावे के कारण भारत संघ को मुकदमेबाजी करने के लिए मजबूर किया गया था, एकल न्यायाधीश ने एक करोड़ रुपये की लागत का फैसला सुनाया। 50, (पचास हजार रुपये) प्रत्यर्थी के पक्ष में, वित्तीय आदेश की तारीख से चार

सप्ताह के भीतर देय और गैर-अनुपालन के मामले में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

“4. मैं पूरे पुरस्कार से गुजरा हूं। पुरस्कार. इस दावे के अंतर्गत नुकसान के रूप में 12.

5. मध्यस्थता कार्यवाहियों के इस दृष्टिकोण में। 7. *** मैं पुरस्कार पर आपत्तियों को स्वीकार करता हूं और मध्यस्थ के दिनांकित पुरस्कार को अलग कर दिया जाता है और दावा 12 के अंतर्गत ठेकेदार का दावा तदनुसार खारिज हो जाएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ 1,000 रुपये का खर्च देता हूं। तदनुसार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, मैं इसे लागत पर ब्याज देने के लिए मानता हूं। "ई) विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों से असंतुष्ट, अपीलार्थी ने 691 की खंड पीठ के समक्ष अपील की।

मेसर्स यूनिब्रॉस बनाम ऑल इंडिया रेडियो दीपांकर दत्ता, जे.

अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत उच्च न्यायालय। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अपील को खारिज करते हुए, खंड पीठ का विचार था कि अपीलार्थी की ओर से उस अवधि के दौरान लाभ के नुकसान की याचिका का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था जब काम लंबा था; इसलिए मध्यस्थ द्वारा वापस किए गए निर्णय विधि के विपरीत हैं, विशेष रूप से अनुबंध अधिनियम जो लाभ के नुकसान से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। कोई असंवेदनशीलता या अवैधता नहीं पाए जाने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को स्वीकार कर लिया गया, और अपील को किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया।

दलों की प्रस्तुतियाँ

5. एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ के फैसलों पर आपत्ति जताते हुए, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री समीर रोहतगी ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं:

क) विद्वान मध्यस्थ अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य को सावधानीपूर्वक देखने के बाद एक न्यायसंगत और तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा था और किसी भी विकृति या मनमौजी के अभाव में, अदालतें निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। संबद्ध बिल्डरों पर भरोसा करना

बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण 1, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया

कि मध्यस्थ साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा का एकमात्र न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय, अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत, विकृति के अभाव में मध्यस्थता पुरस्कारों में हस्तक्षेप करके प्रथम अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

ख) भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बनाम। एल. के. आहूजा 2 को रखा गया था

इस तर्क का समर्थन कि उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कारों में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निर्णय के विशिष्ट अंश पर भरोसा रखा, जिसे संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे निकाला गया है:

“11...जब मध्यस्थ ने अभिवचनों, उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और अनुबंध की शर्तों पर अपना दिमाग लगाया है, तो न्यायालय के लिए पुनर्मूल्यांकन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

1 (2015) 3 एससीसी 49 2 (2004) 5 एससीसी 109

692

/

[2023] 14 एस सी आर।

मामला मानो यह एक अपील थी और भले ही दो विचार संभव हों, मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रबल होगा। जब तक एक मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार को एक उचित व्यक्ति द्वारा दिया गया पुरस्कार कहा जा सकता है, तब तक किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां एक मध्यस्थ समझौते की शर्तों को पार करता है या किसी भी साक्ष्य के अभाव में एक पुरस्कार पारित करता है, जो पुरस्कार के सामने स्पष्ट है, उसे अलग किया जा सकता है। "

ग) धारा 34 के अनुसार, एक पुरस्कार को संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल प्रावधान में उल्लिखित विशिष्ट आधारों के अंतर्गत अलग रखा जा सकता है। 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के विपरीत, जिसने स्पष्ट रूप से संशोधन की अनुज्ञात थी, 1996 का अधिनियम, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 1985 पर UNCITRAL मॉडल विधि पर आधारित है, न्यायालय को धारा 34 के अंतर्गत पुरस्कारों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह मध्यस्थता पुरस्कारों में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के विधायी इरादे के साथ संरेखित होता है। उक्त के समर्थन में रिलायंस

परियोजना निदेशक, एन. एच. ए. आई. बनाम एम. हकीम और अन्य 3 पर विवाद रखा गया था।

घ) मेसर्स ए. टी. बृज पॉल सिंह और अन्य बनाम गुजरात राज्य 4 पर भरोसा किया गया था

यह प्रस्तुत करने पर कि एक ठेकेदार शेष कार्य पर अपेक्षित लाभ के नुकसान के लिए हर्जाने का हकदार है और संक्षिप्त विवरण में जाने के बजाय नुकसान की राशि का आकलन करने के लिए केवल एक व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है; और

ई) हडसन के सूत्र को कानूनी स्वीकृति मिल गई है और आमतौर पर अदालतों और अन्य न्यायिक निकायों द्वारा लाभ के नुकसान का निर्णय देने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि हडसन का सूत्र चालू कार्य के दौरान वास्तविक के

बजाय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय पक्षों द्वारा परिकल्पित अनुबंध में विचार की गई संख्या और आधार पर काम करता है। इसलिए, अपीलार्थी द्वारा कार्य के लिए आवंटित कर्मचारियों, सामग्री और मशीनरी की वास्तविक संख्या की अपीलार्थी द्वारा किए गए लाभ के नुकसान की गणना करने में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

3 (2021) 9 एस. सी. सी. 14 (1984) 4 एस. सी. सी. 59 693

मेसर्स यूनिब्रोस बनाम ऑल इंडिया रेडियो दीपांकर दत्ता, जे.

प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए, अन्यथा हडसन का सूत्र निरर्थक हो जाएगा। रिलायंस को रखा गया था

मैकडमोर्ट इंटरनेशनल इंक बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और

या 5 समर्थन आकर्षित करने के लिए।

6. प्रत्यर्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ("एएसजी", इसके बाद) श्री संजय जैन ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता पुरस्कार मनमाने और सनकी तरीके से पारित किया गया था, और एकल पीठ और खंड पीठ दोनों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय से अपील को खारिज करने और खंड पीठ के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के फैसलों को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए, ए. एस. जी. ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं: (क) वर्तमान मामला विलंब सरलीकरण का होने के कारण, हडसन के सूत्र में लाभ के नुकसान के लिए किसी भी राशि को अधिनिर्णय करने के लिए कोई आवेदन नहीं होगा, जब तक कि पीड़ित पक्ष उक्त सूत्र के आवेदन के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में कोई सबूत नहीं देता है।

ख) हडसन के सूत्र का प्रयोग तीन आवश्यक शर्तों पर निर्भर करता है:

- i. सबसे पहले, ठेकेदार को दिया गया लाभ कहीं और वास्तविक रूप से प्राप्य होना चाहिए था यदि वह उचित समय पर अनुबंध छोड़ने के लिए निशुल्क था।
- ii. दूसरा, ठेकेदार को मूल्य निर्धारण के दौरान अपनी लागतों को लगातार कम नहीं आंकना चाहिए था, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ प्रतिशत उस समय वास्तव में व्यवहार्य था।
- iii. तीसरा, बाजार में बाद में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था, ताकि अनुबंध के समापन के समय ठेकेदार को तुलनीय स्तर की लाभप्रदता का काम उपलब्ध हो।

ग) यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के लिए, संतोषजनक और ठोस साक्ष्य एक अनिवार्य शर्त है, भले ही नुकसान दूरस्थ या काल्पनिक प्रकृति का न हो। लाभ या अवसर के वास्तविक नुकसान की पुष्टि करने वाले ठोस साक्ष्य के अभाव में,

5 (2006) 11 एससीसी 181

[2023] 14 एस सी आर।

यह अनुचित होगा कि ठेकेदार को केवल एक सूत्र के अनुप्रयोग पर पूंजीकरण करने की अनुमति दी जा सके।

घ) वर्तमान मामले में, ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया, अपीलार्थी के नेतृत्व में, किसी भी विश्वसनीय या ठोस साक्ष्य के बिना, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वह उस समय उपलब्ध किसी अन्य अनुबंध के माध्यम से कहीं और ऐसी कीमत अर्जित करने में सक्षम था, जिसे वह अनुबंध के लंबे समय तक चलने के कारण निष्पादित नहीं कर सका; ऐसा पुरस्कार, विकृत होने के कारण, अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (ii) के अंतर्गत भारत की सार्वजनिक नीति के साथ मेल खाता है।

ई) मध्यस्थ के कार्य एक उलझनपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करते हैं: दूसरी ओर, मध्यस्थ ने विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दावा संख्या 10 (अनुबंध अवधि के बाद बढ़ी हुई कीमतों/दरों के लिए मुआवजा) और 11 (प्रतिष्ठान, मशीनरी, सेंटिंग/शटरिंग आदि के लिए मुआवजा) को खारिज करते हुए दावा संख्या 12 के अंतर्गत लाभ के नुकसान के लिए हर्जाना देने के लिए आगे बढ़े। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है: यदि दावा संख्या 10 और 11 का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे, तो कौन सा अन्य सबूत संभवतः दावा संख्या 12 के अंतर्गत लाभ के नुकसान को उचित ठहरा सकता है?

च) हडसन के सूत्र के यांत्रिक अनुप्रयोग से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और एएसजी का समापन प्रस्तुत करना सरकारी खजाने पर बोझ था।

विक्षेपण और निष्कर्ष

7. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का भी अध्ययन किया है।

8. अपील को प्रोफिट्स (दावा संख्या 12) के नुकसान से संबंधित मुआवजे के लिए अपीलार्थी के दावे को खारिज करने की दिशा में निर्देशित किया जाता है। यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि लाभ के नुकसान के लिए अपीलार्थी का दावा परियोजना को पूरा करने में प्रतिवादी के कारण होने वाली देरी से उत्पन्न होता है। यह और स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में प्रश्न े गए लाभ का नुकसान मुख्य रूप से इस आधार पर है कि अपीलार्थी को अनुबंध में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बनाए रखा गया है और उसके संसाधनों को अनुबंध से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए अवरुद्ध किया गया है, वह कोई अन्य कार्य आदेश ले सकता था और कहीं और लाभ अर्जित कर सकता था।

मेसर्स यूनिब्रोस बनाम ऑल इंडिया रेडियो दीपांकर दत्ता, जे.

9. अपीलार्थी की ओर से आगे की गई दलीलें हमें एक आवर्ती मुद्दे को हल करने का काम देती हैं, जो अभूतपूर्व नहीं है, लेकिन लगातार अदालतों का सामना करता है, जिससे उसे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी अनुबंध के निष्पादन में देरी के मामलों में लाभ के नुकसान के दावे की अनुज्ञात जा सकती है।

10. लेकिन इस तरह उठाए गए विवादों के कारण हमें बहुत लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को उठाने वाली अपील के अलावा कि क्या लाभ की हानि के कारण कोई दावा केवल इस आधार पर सफल होने के लिए उत्तरदायी है कि निर्माण अनुबंध के निष्पादन में देरी हुई है, जिसके लिए नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर पहले तथ्यों और परिस्थितियों में देने की आवश्यकता है कि क्या दूसरा पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति (जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, क्योंकि डिबीजन बेंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है) के साथ मेल खाता है।

11. "भारत की सार्वजनिक नीति" का गठन क्या होगा, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है।

ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया। साँ पाइप्स लिमिटेड 6:

“31..., संदर्भ में धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश 'भारत की सार्वजनिक नीति' का व्यापक अर्थ दिया जाना आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक नीति की अवधारणा कुछ ऐसे मामलों को इंगित करती है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित हैं। सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए क्या है या सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए क्या हानिकारक या हानिकारक होगा, यह समय-समय पर अलग-अलग होता रहा है। हालाँकि, जो पुरस्कार, इसके बावजूद, वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, उसे जनहित में नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के पुरस्कार/निर्णय/निर्णय से न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ”

12. इस न्यायालय के बाद के निर्णयों ने "भारत की सार्वजनिक नीति" की व्याख्या की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, भारतीय विधि की मौलिक नीति का अनुपालन, कानून और न्यायिक उदाहरण, न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता, प्राकृतिक न्याय का अनुपालन, वेड्सबरी अनुचितता और पेटेंट अवैधता शामिल हैं। हम इस संबंध में एसोसिएटेड बिल्डर्स (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

13. दूसरा पुरस्कार पढ़ने के बाद, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह पहले पुरस्कार से बेहतर नहीं है, क्योंकि यह जनता के साथ समान रूप से जुड़ा हुआ है

[2023] 14 एस सी आर।

भारत की नीति। हमने विद्वान एकल न्यायाधीश के 20 मई, 2002 के आदेश से देखा है कि पुनः विचार के लिए दावा No.12 को प्रेषित करते समय, मध्यस्थ को चेतावनी दी गई थी कि वह उन कारकों से प्रभावित न हो जो पहला पुरस्कार देते समय उनके दिमाग में थे। मध्यस्थ को भी केवल अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। फिर भी, खेदजनक रूप से, हमें जो लगता है वह यह है कि मध्यस्थ ने उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय की दंड से मुक्ति के साथ उपेक्षा की। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि के भीतर पूरी साइट और ड्राइंग प्रदान नहीं करके अपीलार्थी को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में देरी हुई और साइट को न सौंपना निश्चित रूप से पूरे अनुबंध को दूषित करने वाले अनुबंध का मौलिक उल्लंघन है। इसके बाद उन्होंने अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के हडसन के समर्थन का उल्लेख किया, जो उनके अनुसार, सभी इंजीनियरिंग और भवन अनुबंधों में मानक पाठ था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पहले दौर और दूसरे दौर में मध्यस्थ के दिमाग में जिन कारकों का भार था, वे एक ही हैं। जहाँ तक दावे No.12 का संबंध है, प्रथम पुरस्कार की दर्पण छवि के रूप में ब्रांडेड होने के किसी भी आरोप से बचने के लिए, दूसरा पुरस्कार भाषा में व्यक्त किया गया प्रतीत होता है और पहले वाले से अलग रूप में व्यक्त किया गया है, हालांकि, सार में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

14. यह प्राथमिक है, हालांकि इसे फिर से दोहराया जाना चाहिए कि एक उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय को, जो एक निम्न अदालत के लिए बाध्यकारी है, निम्न अदालत द्वारा अनुग्रह के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न अदालत के लिए रुचिकर न हो। यह सिद्धांत, विशेष रूप से, एक मध्यस्थ और एक बहु-सदस्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर भी लागू होगा, विशेष रूप से जब यह एक सीमित रिमांड का आदेश देने वाले न्यायिक निर्णय (या तो अधिनियम की धारा 34 या धारा 37 के अंतर्गत) का सामना करता है। विधि के न्यायालयों द्वारा किए गए न्यायिक निर्धारण के अधिकार के संदर्भ में, एक मध्यस्थ या एक न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय जो एक बाध्यकारी न्यायिक निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करता है, हमारी राय में, मौलिक सार्वजनिक नीति के साथ निहित है और इसलिए, कायम नहीं रह सकता है।

15. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, भले ही बहुत कम निर्णय लिया जाना बाकी है, हम अपीलार्थी के नुकसान के दावे को संक्षेप में संबोधित करना चाहेंगे।

प्रो. टी.भारत खाना पकाने के कोयले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि लाभ के इस तरह के नुकसान के दावे पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाएगा। यह देखा गया:

मेसर्स यूनिब्रोस बनाम ऑल इंडिया रेडियो दीपांकर दत्ता, जे.

“24. ठेकेदारों के लिए काम पूरा करने के मामले में देरी के कारण कारोबार में कमी के कारण होने वाले लाभ के नुकसान का दावा करना असामान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे यह स्थापित करना चाहिए कि अगर उसे अनुबंध के अंतर्गत देय राशि मिल जाती, तो वह इसका उपयोग किसी अन्य व्यवसाय के लिए कर सकता था जिसमें वह लाभ अर्जित कर सकता था। जब तक ऐसी याचिका नहीं उठाई जाती और स्थापित नहीं की जाती, तब तक लाभ के नुकसान का दावा मंजूर नहीं किया जा सकता था। इस मामले में, ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्ष्य के अभाव में, मध्यस्थ इसे नहीं दे सकता था।”

(हमारा जोर दें) 16। विलंबित अनुबंध या अन्य उपलब्ध अनुबंधों से चूके गए अवसरों से उत्पन्न होने वाले लाभ के नुकसान के दावे का समर्थन करने के लिए, जो अपीलार्थी किसी को भी लेकर कहीं और अर्जित कर सकता था, दावेदार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह सम्मोहक साक्ष्य के माध्यम से एक व्यवहार्य अवसर की उपस्थिति की पुष्टि करे। इस साक्ष्य से यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि अनुबंध को तुरंत निष्पादित किया जाता, तो ठेकेदार अपने मौजूदा संसाधनों का कहीं और उपयोग करके पूरक लाभ प्राप्त कर सकता था।

17. कोई यह पूछ सकता है कि इस तरह के साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता क्या होगी? हमारी राय में, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, इसमें आम तौर पर स्वतंत्र समकालीन साक्ष्य शामिल हो सकते हैं जैसे कि ठेकेदार के पास पाइपलाइन में अन्य संभावित परियोजनाएं जो देरी के लिए नहीं तो शुरू की जा सकती थीं, अनुबंध के लंबे समय तक चलने के कारण ठेकेदार को प्राप्त और अस्वीकार किए गए निविदा अवसरों की कुल संख्या, वित्तीय विवरण, या देरी, समय बढ़ाने और लाभ के नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित अनुबंध में कोई भी खंड। हालांकि यह सूची संपूर्ण नहीं है और इसमें सबूत का कोई अन्य टुकड़ा शामिल हो सकता है कि न्यायालय प्रासंगिक और प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन जो कटौती और सूखी है वह यह है कि लाभ के नुकसान के दावे पर निर्णय लेने में, न्यायालय अंधेरे में अनुमान नहीं लगा सकती है; इसलिए, सबूत की विश्वसनीयता इस तरह के दावे की विश्वसनीयता का प्रमाण है।

18. हडसन का सूत्र, हालांकि स्वीकार्यता प्राप्त करता है और व्यापार में अच्छी तरह से समझा जाता है, लेकिन निर्वात में लागू नहीं होता है। हडसन के सूत्र के साथ-साथ ऑफ-साइट ओवरहेड्स और लाभ के नुकसान के दावों की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य विधियां सीधे ठेकेदार की सटीक लागत को नहीं मापती हैं। इसके बजाय, वे ठेकेदार को होने वाले नुकसान का अनुमान देते हैं।

काफी हो गया है। जबकि ये सूत्र आवश्यकता पड़ने पर सहायक होते हैं, वे अकेले ठेकेदार के लाभ के नुकसान को साबित नहीं कर सकते हैं। वे नुकसान का आकलन करने में उपयोगी होते हैं, लेकिन केवल तभी जब ठेकेदार ने साक्ष्य के साथ दिखाया हो कि लाभ और अवसरों का नुकसान लंबे समय तक चलने के कारण हुआ है।

19. विधि, जैसा कि इसे इस प्रकार खड़ा होना चाहिए, यह है कि लाभ की हानि, लाभप्रदता या सफल होने के अवसरों से संबंधित दावों के लिए, निम्नलिखित शर्तों को स्थापित करने की आवश्यकता होगी: पहला, अनुबंध के पूरा होने में देरी हुई; दूसरा, इस तरह की देरी दावेदार के कारण नहीं है; तीसरा, एक स्थापित ठेकेदार के रूप में दावेदार की स्थिति, जो पर्याप्त परियोजनाओं को संभाल रहा है; और चौथा, लाभप्रदता के नुकसान के दावे को साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत। अभिलेख के अवलोकन पर, हमें संतोष होता है कि चौथी शर्त, अर्थात्, लाभप्रदता के नुकसान के दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य वर्तमान मामले में अपूर्ण है।

20. ऊपर उल्लिखित कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम पुरस्कार में हस्तक्षेप किया गया था। मध्यस्थ, उच्च न्यायालय द्वारा किए गए ऐसे पूर्व निर्धारण को देखते हुए, अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को हर्जाना दे सकता था। कहने के लिए, ऐसा कोई भी नहीं था जो सबूत पर लाभ के नुकसान के लिए हर्जाने के लिए पुरस्कार में परिवर्तित हो सकता था। हर्जाने के लिए एक दावा, चाहे सामान्य हो या विशेष, निश्चित रूप से दावेदार को पर्याप्त चोट लगने के प्रमाण के बिना एक पुरस्कार में परिणत नहीं हो सकता है। प्रश्न मध्यस्थता पुरस्कार, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से अवैध है क्योंकि यह किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और इस प्रकार, पूरी तरह से विकृत है; इसलिए, फिर से, यह अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) द्वारा विचारित "भारत की सार्वजनिक नीति" के साथ मेल खाता है।

21. उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। वही खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई लागत को आसान बना दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे